प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

सचिवालय सुधार

क) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना

ख) ई-ऑफिस

ग) स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी

मासिक रिपोर्ट | जून 2025

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विषय सूची

1. मुख्य- मुख्य बातें, जून 2025... 1
I. ई ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन 1
II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियाँ (जून 2025)... 2
III. लंबित मामलों में कमी 2
2. सुशासन परिपाटियों की प्रतिकृति: राज्य स्तरीय उपलब्धियां 3
3. औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण (डिलेयरिंग) 4
3.1. डिलेयरिंग प्रवृत्ति (जून 2025)... 4
3.2. डिलेयरिंग की स्थिति (जून - 2025) 5
4. ई-ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन 7
4.1 ई-ऑफिस विश्लेषण ... 7
4.2. ई-फाइल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी 8
4.3. ई-फाइल में प्रस्तुत करना (जून 2025)... 9
4.4. अंतर विभागीय फ़ाइल आवाजाही 9
4.5. ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का % शेयर) 10
4.6. ई-ऑफिस विश्लेषण 11
5. विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना 15
5.1. कुल अर्जित राजस्व 15
5.2 स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व (जून 2025)... 16
5.3. खाली हुआ स्थान (जून 2025)... 16
क . शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित राजस्व 17
5.4. स्वच्छता अभियान स्थल (जून 2025)... 18
5.5. छँटाई की गई फिजिकल फाइलें (जून 2025)... 18

6. पहले- बाद में 19

7. सर्वश्रेष्ठ परिपाटियाँ - नागरिक अभिमुख परिपाटियाँ 21

8. मंत्रालयों/विभागों का मापदंड - वार कार्य निष्पादन 22

9. मुख्य केंद्र बिन्दु: डाक विभाग 24

क. परिचय 24

ख. विशेष अभियान के दौरान मुख्य उपलब्धियां 24

ग. ग्राहक अभिमुख प्रमुख डिजिटल पहल 25

घ. झलकियां 26

10. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर कार्यालय ज्ञापन 29

11. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन 30

12. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन 31

13. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन 32

अनुलग्नक I : अपलोड नहीं किए गए आँकड़े 34

अनुलग्नक II: संकेताक्षरों की सूची 35

1 मुख्य मुख्य बातें, जून 2025

I. ई-ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन

72

मंत्रालयों/विभागों के पास कम से कम **80%** ई-फाइलें हैं

19

मंत्रालयों/विभागों के पास **100%** ई- रिसीट्स है

22

मंत्रालयों/विभागों का औसत ट्रांजैक्शन स्तर **4** अथवा 4 से कम है।

ई-फाइलों का उपयोग (%)

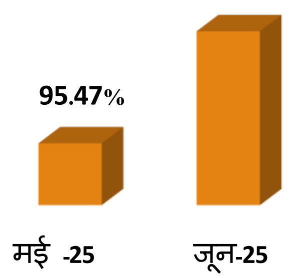

जून **2025: 5,07,562** में से **4,80,885** ई- रिसीट्स थीं

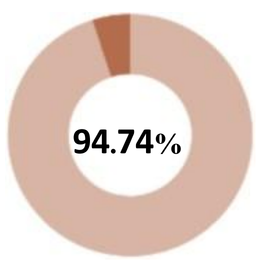

औसत ट्रांजैक्शन स्तर

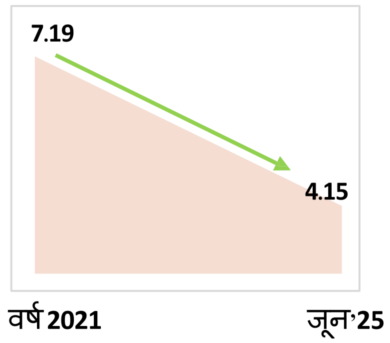

सक्रिय, बंद की गई और कुल ई फाइलों के मासिक आँकड़े

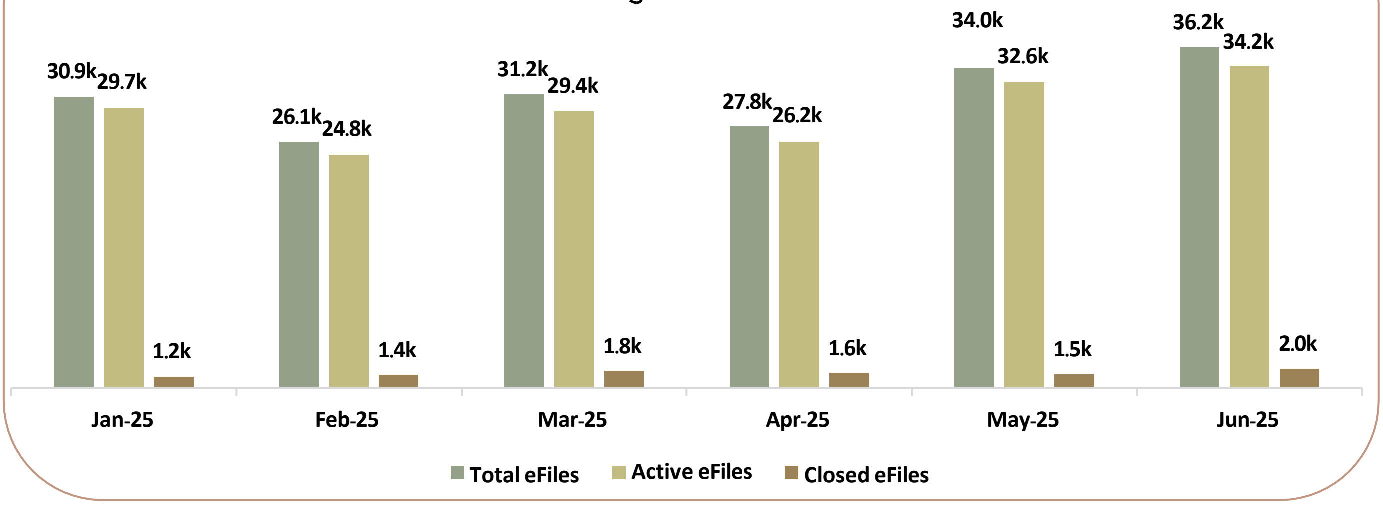

II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियाँ (जून 2025)

8,128

स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया

11,66,891

वर्ग फुट स्थान खाली हुआ

56,07,35,203

स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व

III. लंबित मामलों में कमी

निपटान

- ✓ **4,70,192** जन शिकायतें
- ✓ **16,934** जन शिकायत अपीलें
- ✓ **1,229**संसद सदस्यों से संदर्भ
- ✓ **230** राज्य सरकारों से संदर्भ
- ✓ **72** आईएमसी संदर्भ
- ✓ **726** पीएमओ संदर्भ

पूरे किए गए संसदीय आश्वासन

83

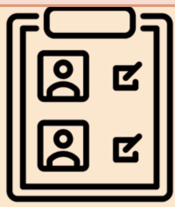

अभिलेख प्रबंधन

82,958 फिजिकल फ़ाइलों की समीक्षा गई तथा **52,427** फ़ाइलों की छँटाई की गई।

2 सुशासन परिपाटियों की प्रतिकृति: राज्य स्तरीय उपलब्धियां

पृष्ठभूमि और उपलब्धियां

केंद्रीय स्तर पर किए गए सचिवालय सुधारों को अब महाराष्ट्र और हरियाणा द्वारा सक्रिय रूप से दोहराया जा रहा है, जो केंद्रीय सचिवालय की परिधि से बाहर इन पहलों के बढ़ते प्रभाव और प्रासंगिकता को दर्शाता है। 29 अप्रैल 2025 को पटना में शुरू किया गया स्वच्छ बिहार पोर्टल, केंद्रीय पहलों के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन में सफल ट्रांजिशन का नवीनतम उदाहरण है। एससीडीपीएम पोर्टल (लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान) की सबसे करीबी राज्य-विशिष्ट प्रतिकृति के रूप में डिज़ाइन करके, इसे एनआईसी की डीएआरपीजी तकनीकी टीम के सहयोग से बिहार के प्रशासनिक संदर्भ के अनुरूप तैयार किया गया है। यह पोर्टल बिहार के सभी विभागों में स्वच्छता, शिकायत निवारण और डिजिटल फ़ाइल प्रबंधन की संरचित निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, जिससे जमीनी स्तर पर सुशासन परिपाटियों को संस्थागत रूप दिया जा सकता है।

स्वच्छ पोर्टल की प्रमुख कार्यक्षमताएँ

रिकॉर्ड प्रबंधन

स्वच्छता अभियान की रिपोर्टिंग

स्क्रैप निपटान ट्रैकिंग

एकीकृत निगरानी डैशबोर्ड

केंद्र-राज्य प्रतिकृति

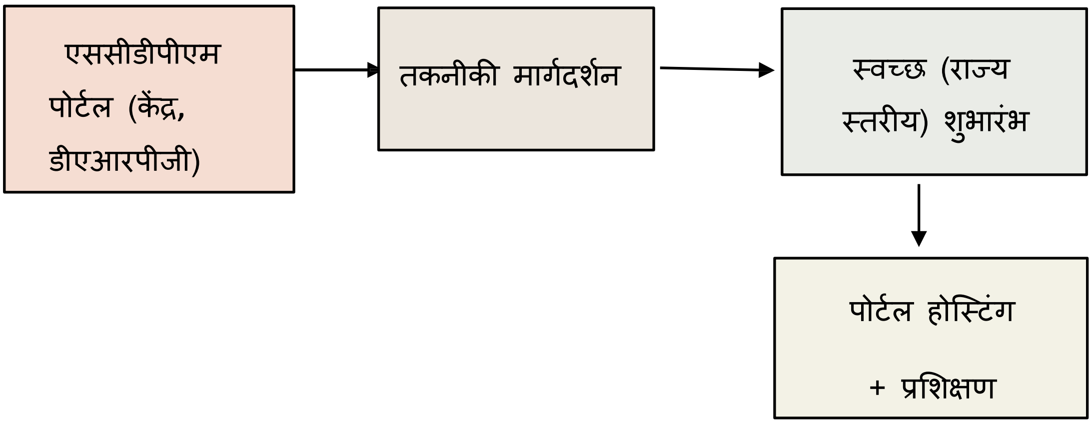

मीडिया कवरेज

3 औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण (डिलेयरिंग)

मुख्य व्याख्या

केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 2021 के 7.19 से घटकर जून 2025 में केवल 4.15 रह गया है, जिससे प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और दक्षता बढ़ेगी।

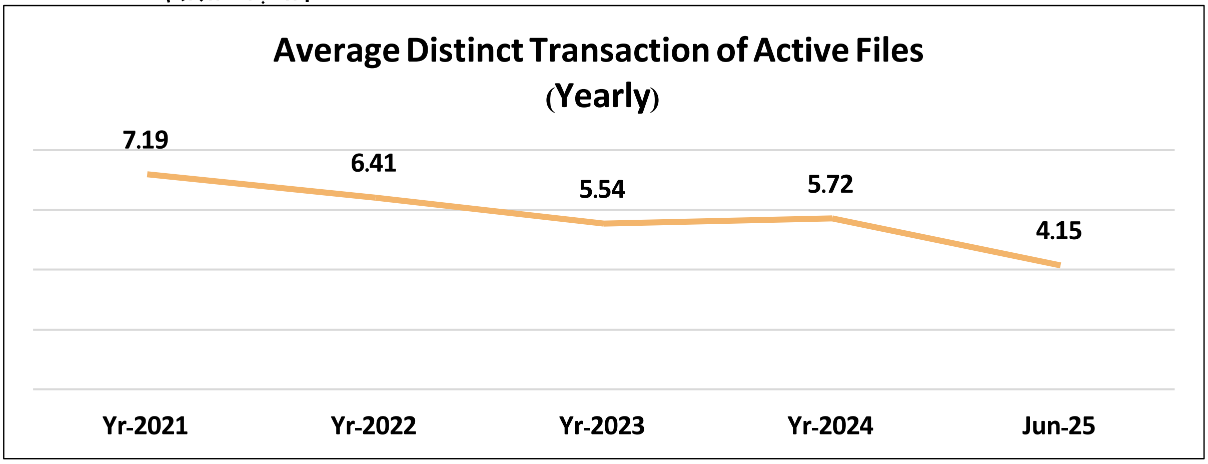

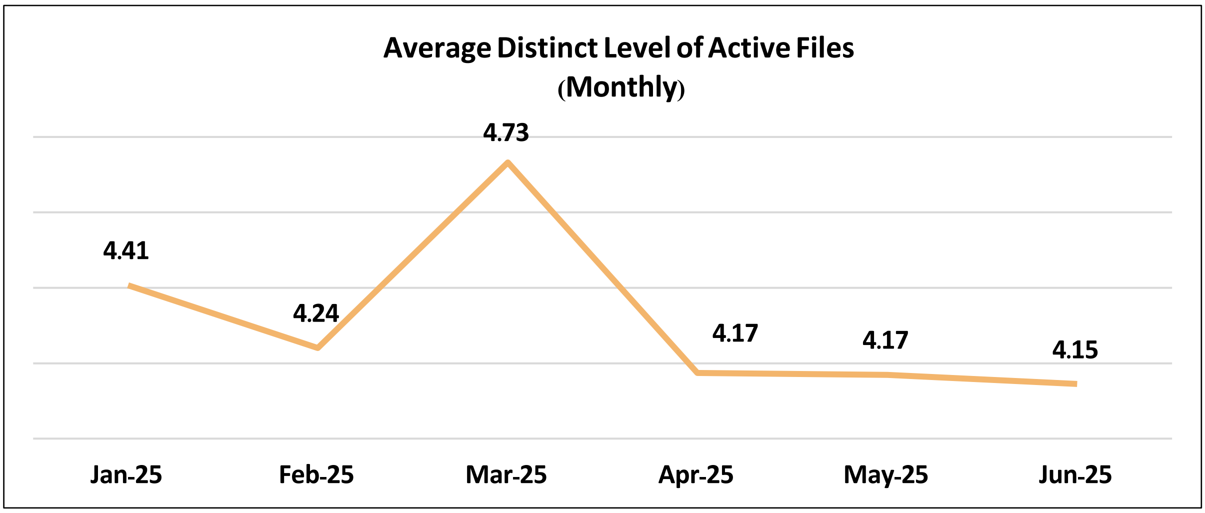

3.1 डिलेयरिंग प्रवृत्ति (जून 2025)

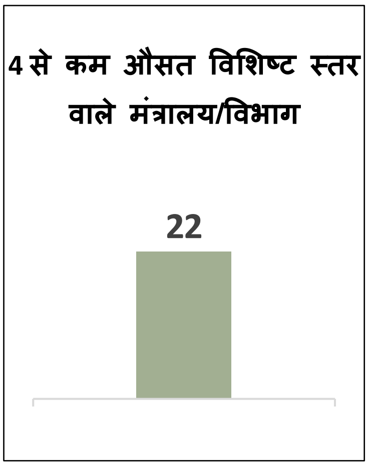

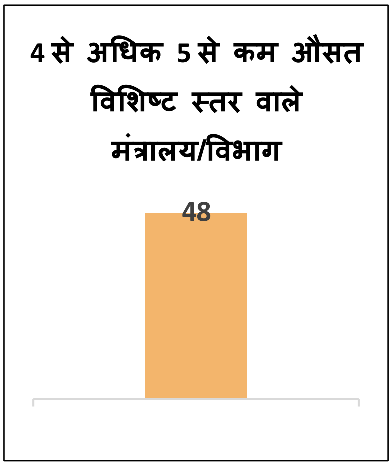

3.2. डिलेयरिंग की स्थिति (जून- 2025)

निम्नलिखित ग्राफ जून, 2025 के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तरों को दर्शाता है :

क. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर <_ 4 तक है

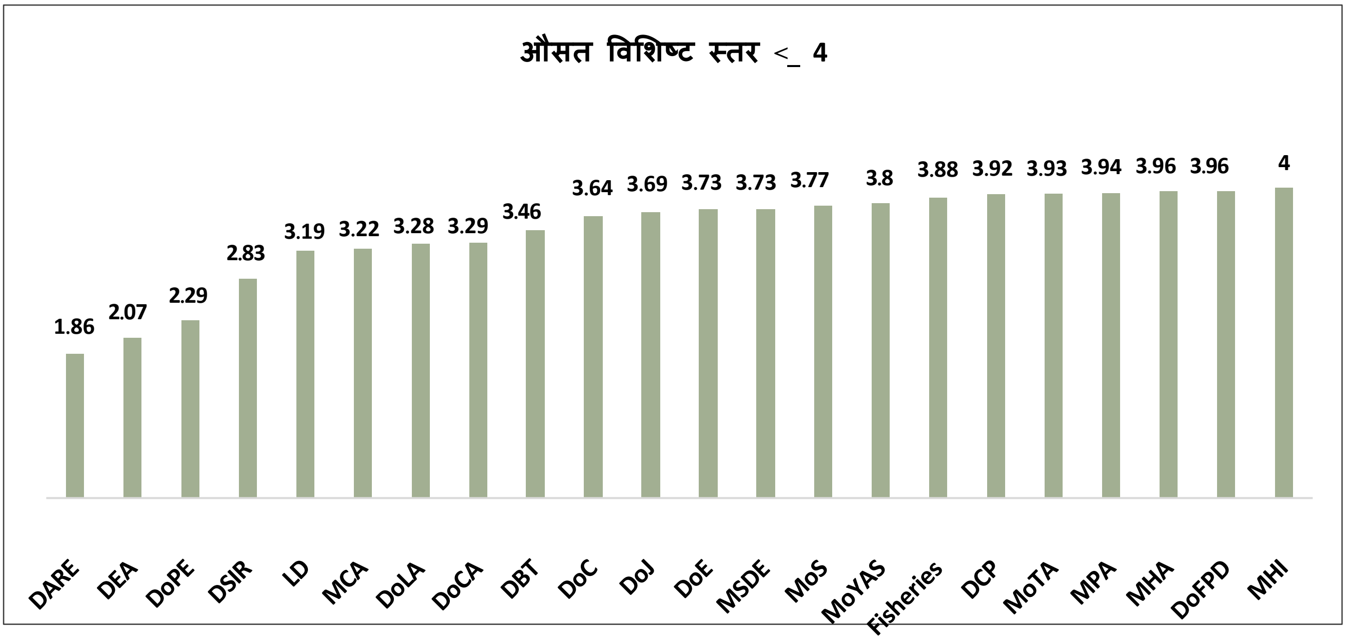

ख. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 4 से अधिक तथा 5 से कम या बराबर है

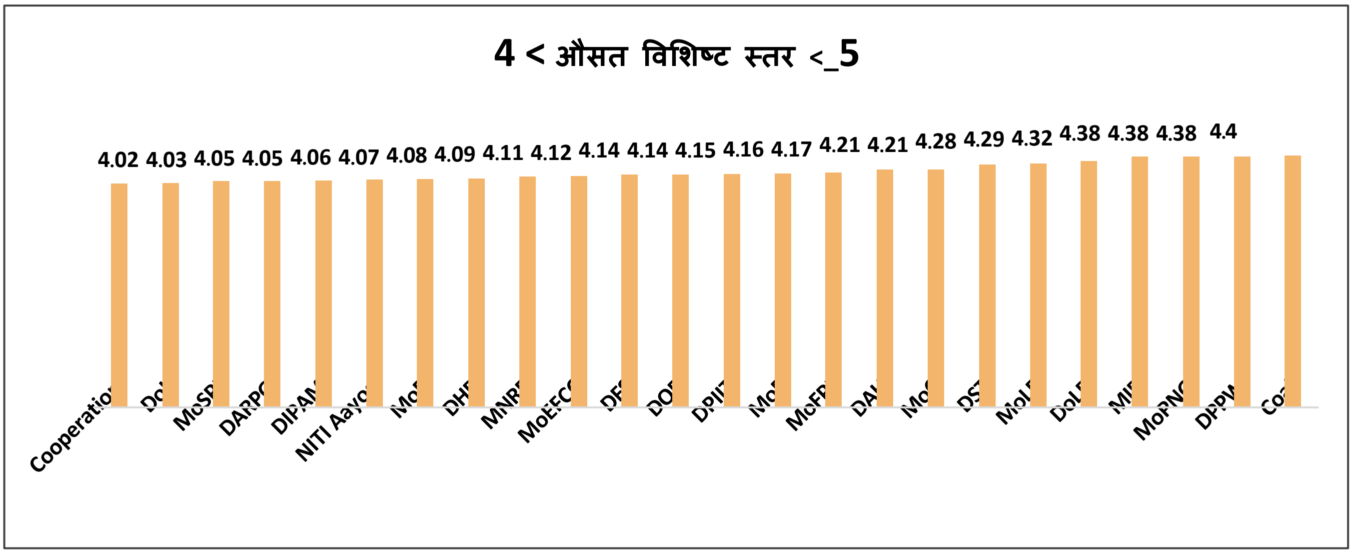

- **औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर >4 और ≤ 5 वाले मंत्रालय/विभाग (जारी)**

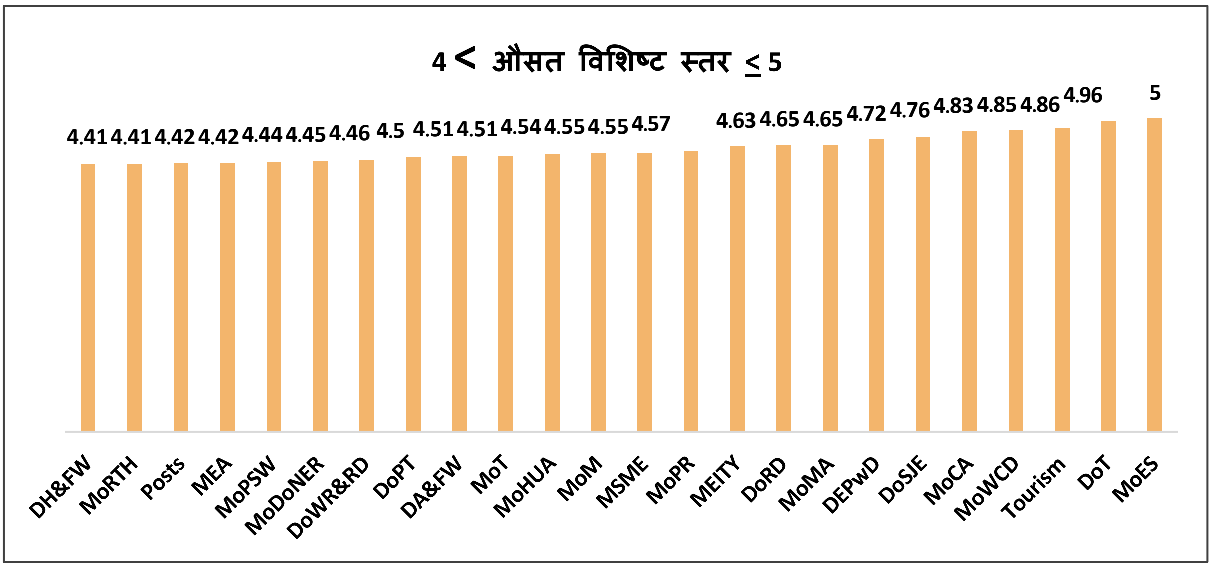

ग. 5 से अधिक औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग

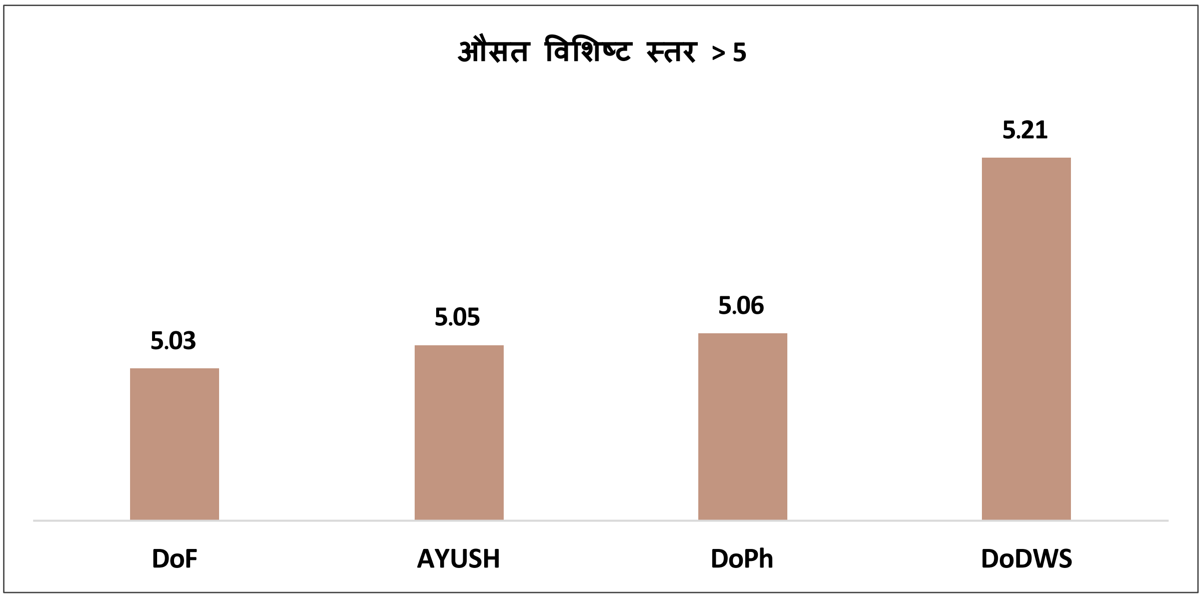

केवल 4 मंत्रालयों/विभागों का औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 5 से अधिक है - उर्वरक विभाग (डीओएफ) का 5.03, आयुष मंत्रालय का 5.05, औषध विभाग का 5.06 तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का 5.21 है।

4 ई-ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन

4.1 ई -ऑफिस विश्लेषण

➢ ई-ऑफिस विश्लेषण डैशबोर्ड (https://vishleshan.eoffice.gov.in/) का शुभारम्भ दिनांक 19 दिसंबर, 2023 को किया गया।

यह डैशबोर्ड निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- गहन डाटा विश्लेषण को आसान बनाने और निर्णयन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए रियल टाइम मेट्रिक्स
- डाटा विज़ुअलाइज़ेशन और ट्रेंड के मूल्यांकन के माध्यम से निर्णयन प्रक्रिया में वृद्धि
- ई-ऑफिस को और अधिक सुव्यवस्थित एवं मजबूत बनाने के लिए डाटा विश्लेषण
- आईईडीएम के प्रभावी तथा व्यापक कार्यान्वयन को सुगम बनाना।

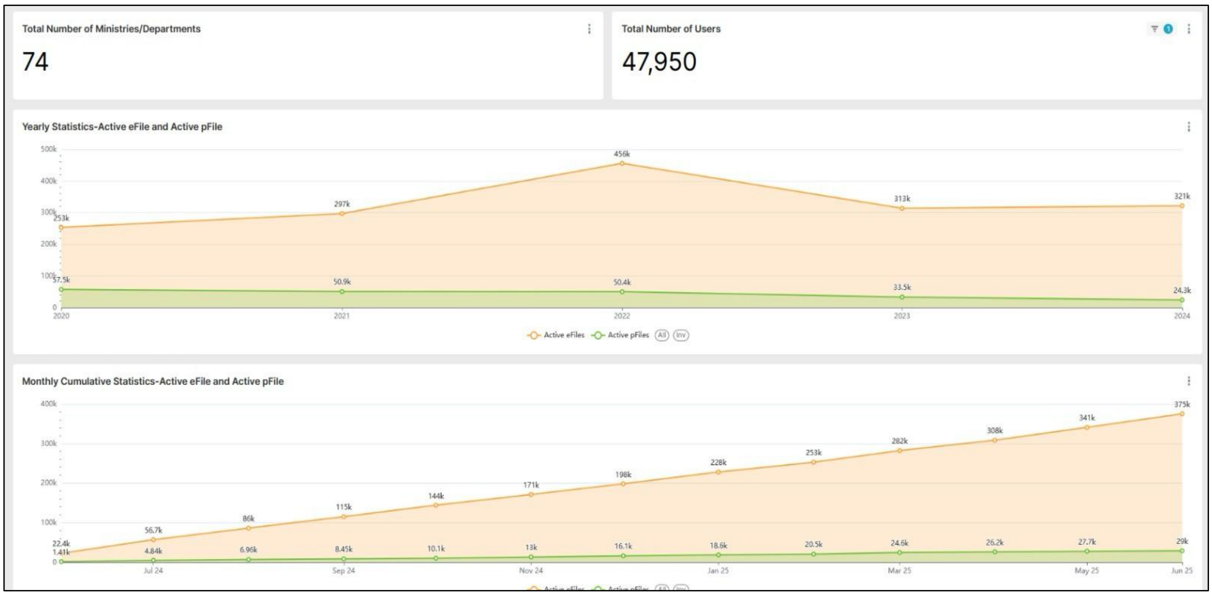

ई-ऑफिस विश्लेषण डैशबोर्ड इंटरफ़ेस

यूआरएल: https://vishleshan.eoffice.gov.in/

डैशबोर्ड केवल एनआईसी नेट पर उपलब्ध है। वर्तमान में, यह भारत सरकार के सभी सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (जिनके संबंध में केवल एनआईसी ईमेल) और मोबाइल नंबर के विवरण के साथ एनआईसी से विशिष्ट अनुरोध किया जाना है) के लिए सुलभ है।

4.2 ई-फाइल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी

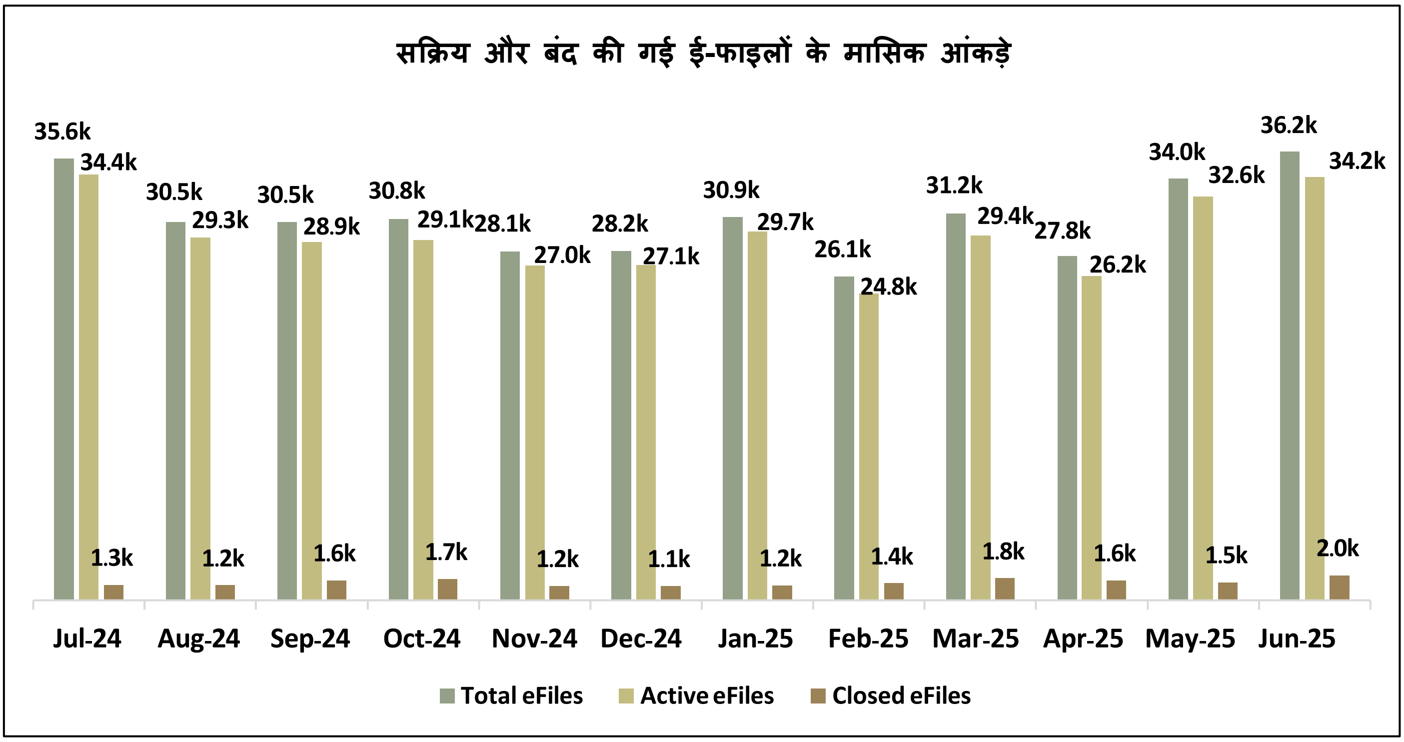

जुलाई 2024 से जून 2025 तक ई-फाइलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, **जो जून 2025 में 36.2** हजार हो गई है। यह मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के निरंतर अपनाए जाने और सक्रिय उपयोग को दर्शाता है, जिसमें सक्रिय और बंद की गई फाइलों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है - जो ***बेहतर डिजिटल वर्कफ़्लो और फ़ाइल प्रबंधन को दर्शाता है।***

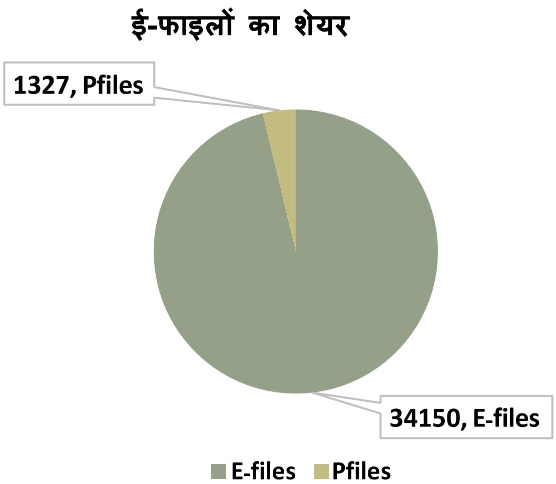

जून **2025** में कुल सक्रिय फाइलों में ई-फाइलों का हिस्सा **96.26%** था, जो फिजिकल फाइलों की तुलना में डिजिटल फाइलों के अधिक उपयोग को दर्शाता है।

4.3. ई-फाइल में प्रस्तुत करना (जून 2025)

जून 2025 माह के लिए सक्रिय ई-फाइलों में <90% शेयर वाले मंत्रालय/विभाग:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	ई-फाइल्स का % शेयर
1	दूरसंचार विभाग	89.46%
2	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	84.52%
3	गृह मंत्रालय	67.73%
4	राजभाषा विभाग	10.53%

4.4. अंतर-विभागीय फ़ाइल आवाजाही

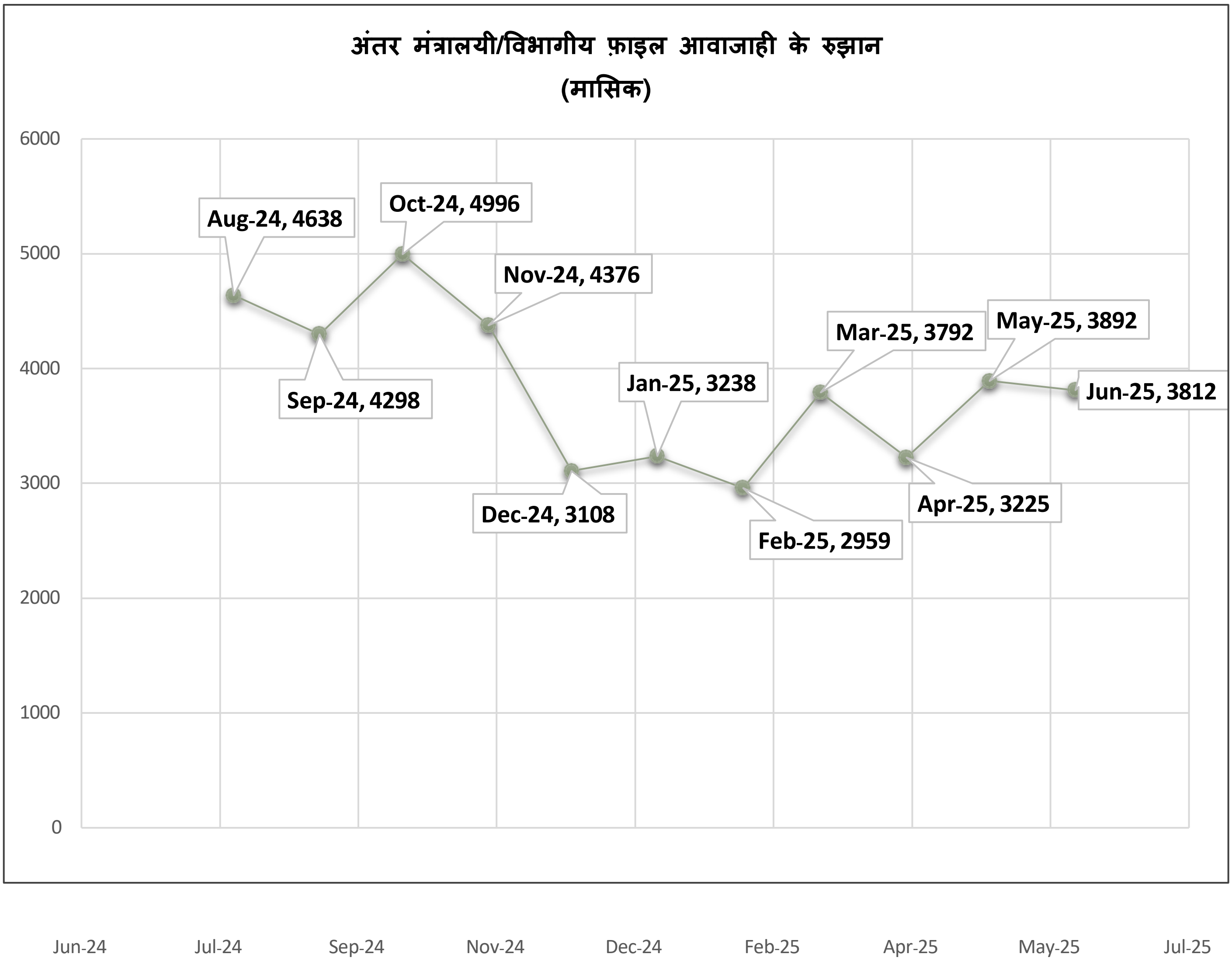

- **अंतर-मंत्रालयी फ़ाइल आवाजाही में अग्रणी मंत्रालय/विभाग – जून 2025**

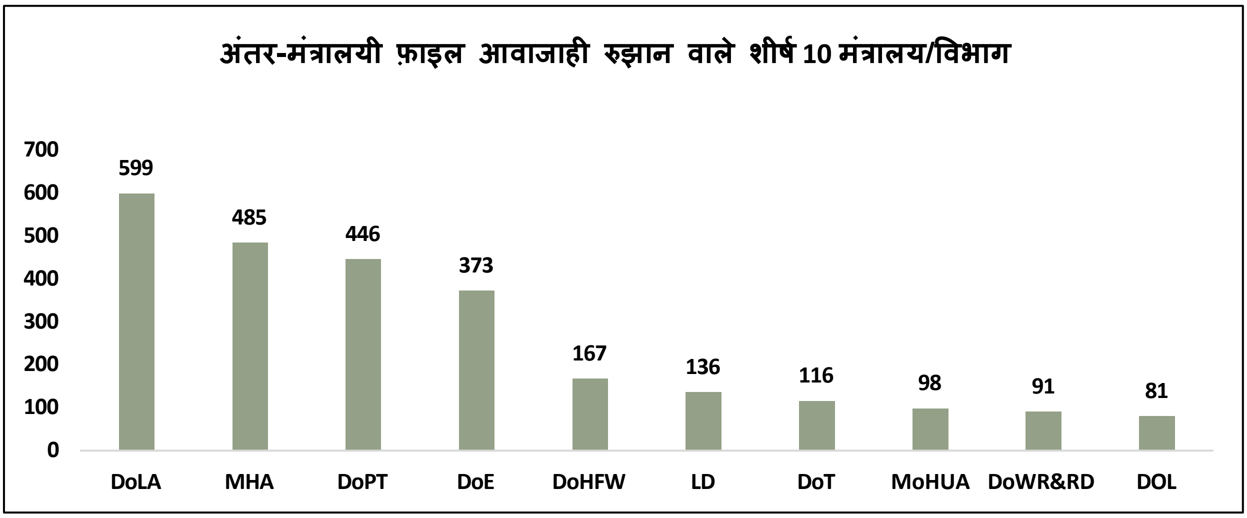

4.5. ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का % शेयर)

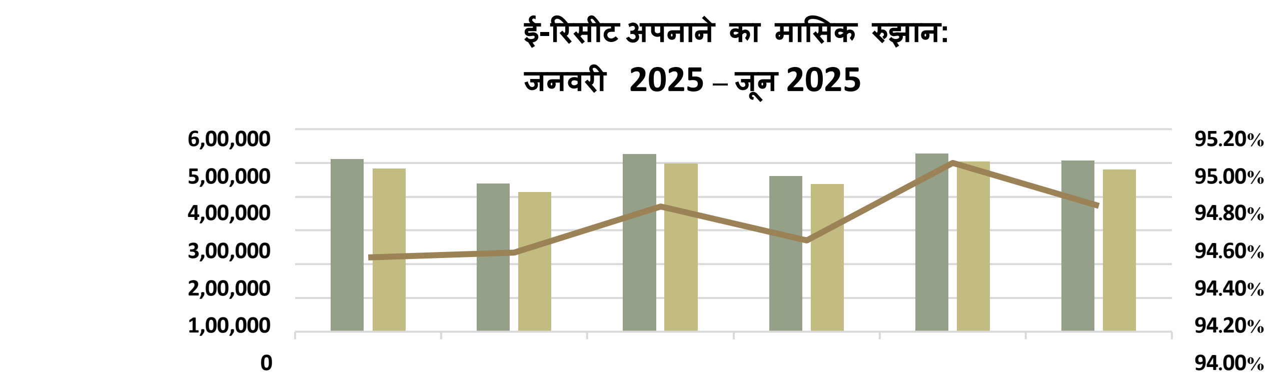

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
कुल प्राप्त रिसीट्स	5,11,636	4,38,248	5,26,379	4,61,603	5,29,070	5,07,562
कुल प्राप्त ई-रिसीट्स	4,83,198	4,14,013	4,98,672	4,36,387	5,02,606	4,80,885
ई-रिसीट्स का %	94.44%	94.47%	94.74%	94.54%	95.00%	94.74%

कुल प्राप्त रिसीट्स   कुल प्राप्त ई-रिसीट्स   ई-रिसीट्स का %

पिछले छह महीनों में ई-रिसीट्स का शेयर लगातार 94% से ऊपर बना हुआ है, जो जून 2025 में 94.74% के उच्चतम स्तर पर है - यह मंत्रालयों/विभागों में रिसीट प्रबंधन में निरंतर डिजिटल अडॉपशन का संकेत है।

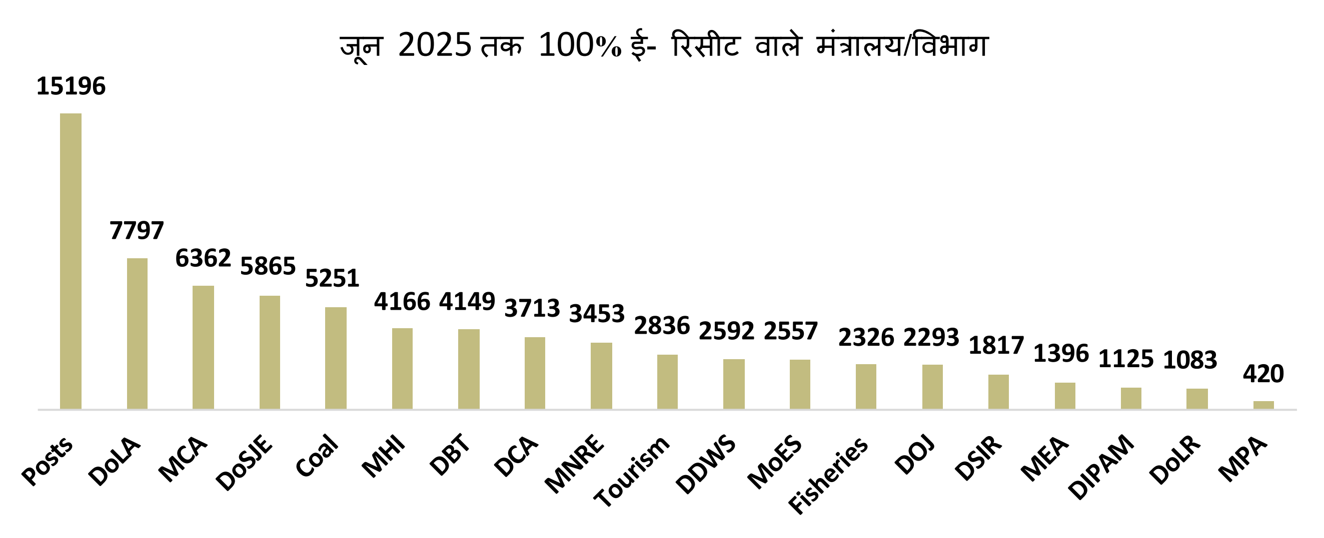

4.6. ई - ऑफिस विश्लेषण

जून 2025 के लिए मंत्रालय-वार विश्लेषण का सारांश इस प्रकार है:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 औसत विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
1	डीईए - वित्त मंत्रालय	99.97%	97.56%	6.75%
2	डीओएचएफडब्ल्यू विभाग - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	98.60%	93.44%	-
3	गृह मंत्रालय	67.73%	79.12%	34.05%
4	विधायी कार्य विभाग	100.00%	100.00%	10.52%
5	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	99.91%	96.76%	-
6	शिक्षा मंत्रालय	96.45%	98.80%	42.15%
7	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	99.78%	99.98%	38.78%
8	विधायी विभाग	100.00%	88.60%	9.38%
9	वाणिज्य विभाग	99.76%	97.31%	27.47%
10	डीओई - वित्त मंत्रालय	95.32%	67.00%	27.01%
11	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	84.52%	88.65%	45.68%
12	डाक विभाग	100.00%	100.00%	37.43%
13	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग	99.87%	98.73%	37.44%
14	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	100.00%	99.85%	41.29%
15	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	98.96%	99.88%	32.94%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 औसत विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
16	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	98.02%	99.71%	43.11%
17	दूरसंचार विभाग	89.46%	83.40%	50.09%
18	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	91.44%	76.95%	46.46%
19	डीएफएस - वित्त मंत्रालय	100.00%	92.88%	33.49%
20	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	99.79%	93.89%	26.43%
21	नीति आयोग	100.00%	97.76%	33.92%
22	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	24.45%
23	जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	100.00%	99.95%	45.11%
24	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	99.74%	99.99%	42.33%
25	आयुष मंत्रालय	93.97%	80.78%	56.75%
26	विदेश मंत्रालय	100.00%	100.00%	40.17%
27	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	99.44%	91.15%	41.69%
28	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	99.43%	99.95%	34.93%
29	पशुपालन और डेयरी विभाग	100.00%	99.87%	34.65%
30	डीओआर - वित्त मंत्रालय	98.13%	85.64%	28.41%
31	खान मंत्रालय	100.00%	99.92%	38.22%
32	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	99.36%	96.42%	44.48%
33	नागर विमानन मंत्रालय	100.00%	99.73%	60.15%
34	ग्रामीण विकास विभाग	99.63%	99.96%	48.68%
35	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	100.00%	100.00%	5.42%
36	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	98.79%	98.91%	40.48%
37	संस्कृति मंत्रालय	99.57%	96.15%	38.27%
38	विद्युत मंत्रालय	98.28%	99.91%	35.24%
39	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	100.00%	99.97%	53.47%
40	पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	100.00%	99.91%	46.69%
41	पर्यटन मंत्रालय	100.00%	100.00%	52.87%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 औसत विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
42	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	100.00%	100.00%	51.93%
43	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	98.48%	86.93%	53.85%
44	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	100.00%	100.00%	59.21%
45	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	100.00%	99.82%	35.67%
46	डीएचआर विभाग - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	96.65%	90.68%	-
47	वस्त्र मंत्रालय	98.81%	79.70%	38.36%
48	इस्पात मंत्रालय	93.71%	99.01%	33.13%
49	कोयला मंत्रालय	100.00%	100.00%	41.61%
50	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	100.00%	100.00%	33.33%
51	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	100.00%	99.88%	40.29%
52	उर्वरक विभाग	99.34%	99.82%	54.23%
53	मत्स्य विभाग	100.00%	100.00%	32.81%
54	सहकारिता मंत्रालय	99.26%	90.51%	35.20%
55	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	100.00%	99.90%	37.40%
56	उपभोक्ता मामले विभाग	100.00%	100.00%	23.15%
57	पंचायती राज मंत्रालय	100.00%	99.95%	45.36%
58	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	100.00%	100.00%	21.25%
59	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	100.00%	95.19%	34.52%
60	जनजातीय कार्य मंत्रालय	98.98%	99.38%	31.82%
61	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	98.96%	88.45%	46.51%
62	भारी उद्योग मंत्रालय	100.00%	100.00%	30.12%
63	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	98.72%	99.92%	29.63%
64	औषध विभाग	94.81%	99.64%	58.46%
65	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग	100.00%	99.03%	53.45%
66	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	100.00%	100.00%	56.86%
67	न्याय विभाग	100.00%	100.00%	22.92%
68	भूमि संसाधन विभाग	100.00%	100.00%	44.74%
69	संसदीय कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	41.94%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 औसत विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
70	दीपम - वित्त मंत्रालय	100.00%	100.00%	41.18%
71	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	92.00%	97.15%	33.33%
72	सार्वजनिक उद्यम विभाग	100.00%	99.82%	-
73	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	100.00%	99.53%	7.14%
74	राजभाषा विभाग	10.53%	22.04%	27.27%

जिन मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 5 से अधिक है, द्वारा डिलेयरिंग/डेलिगेशन की समीक्षा की जानी है।

5 विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना

कुल उपलब्धियाँ (2021 -जून 2025)

मापदंड	एस.सी. 1.0 - एस.सी. 4.0	दिसम्बर'24 - मई'25	जून 25	कुल
अर्जित राजस्व (करोड़ रुपए में)	2,364.05	799.92	56.07	**3220.04**
खाली हुआ स्थान (लाख वर्ग फुट में)	643.82	35.93	11.67	**691.42**
स्वच्छता अभियान स्थल	11,49,935	39,724	8,128	**11,97,787**
छंटनी की गई फाइलें (लाख में)	131.4	5.2	0.52	**137.12**

ये आँकड़े विशेष अभियानों (एस.सी. 1.0 - एस.सी. 4.0) और सचिवालय सुधारों की निरंतर गति को दर्शाते हैं, जो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और मंत्रालयों/विभागों में स्वच्छता को बढ़ावा देने में सहायक हैं। जून, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, संचयी उपलब्धियों में शामिल हैं: स्क्रैप निपटान से **₹3220.04** करोड़ की आय हुई, **691.42** लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ, **11.97** लाख से ज़्यादा स्थलों को स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत लाया गया और **137.12** लाख फाइलों का निपटान किया गया। दिसंबर, **2024** से जून, **2025** तक हुई निरंतर प्रगति स्वच्छता के संस्थागतकरण और दैनिक शासन में दक्षता-उन्मुख परिपाटियों की पुष्टि करती है।

5.1. कुल अर्जित राजस्व (करोड़ रू में)

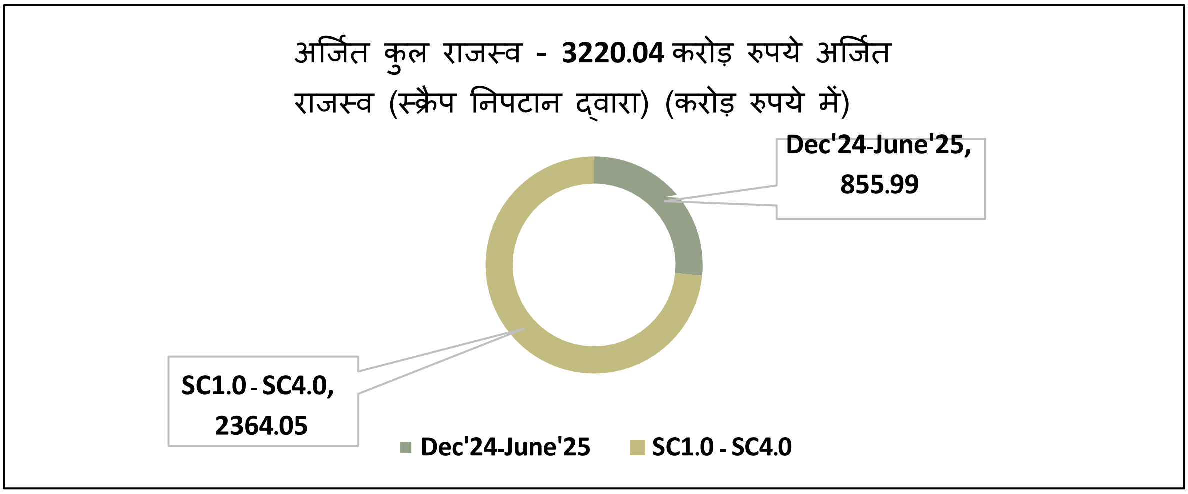

स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित कुल **₹3220.04.97 करोड़** राजस्व में से, **₹855.99 करोड़ दिसंबर, 2024-जून 2025** के दौरान ही प्राप्त हुए, जो विशेष अभियान **एस.सी. 1.0 - एस.सी. 4.0** से आगे निरंतर गति को दर्शाता है, जिसने पहले यह **₹2364.05 करोड़** था।

5.2 स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व (जून, 2025)

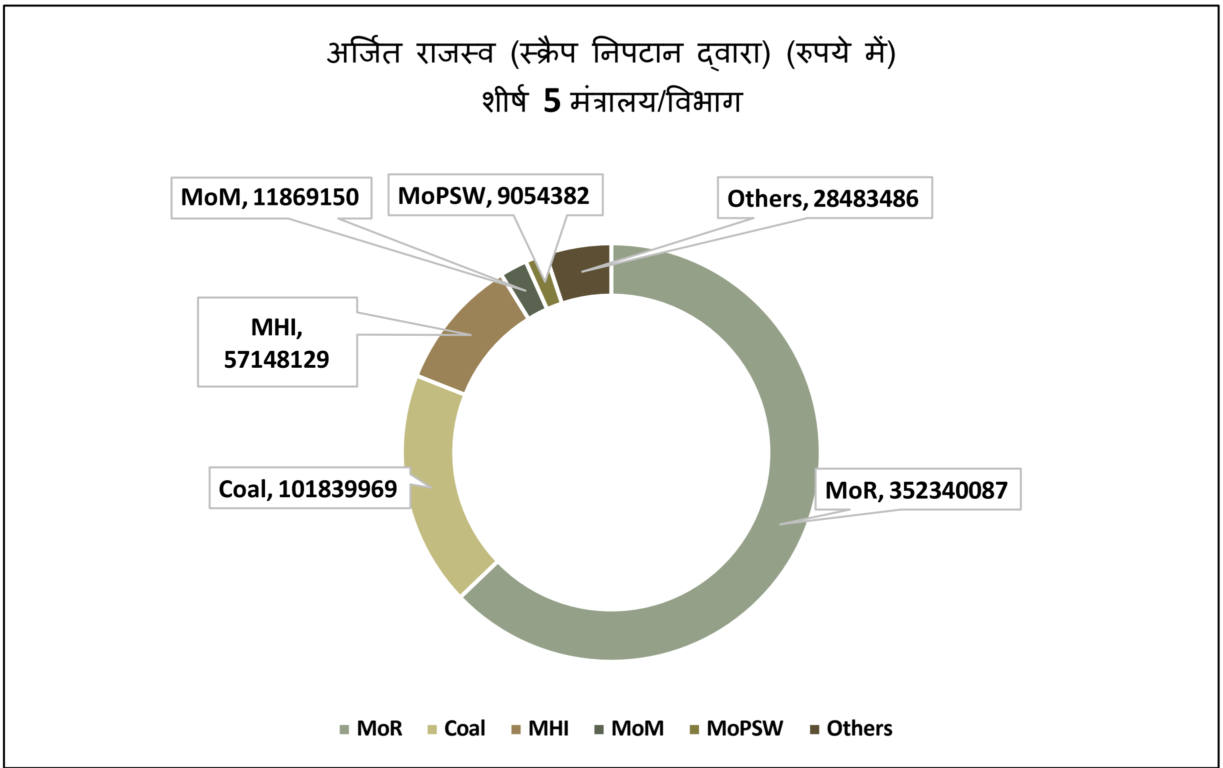

5.3 खाली हुआ स्थान (जून 2025)

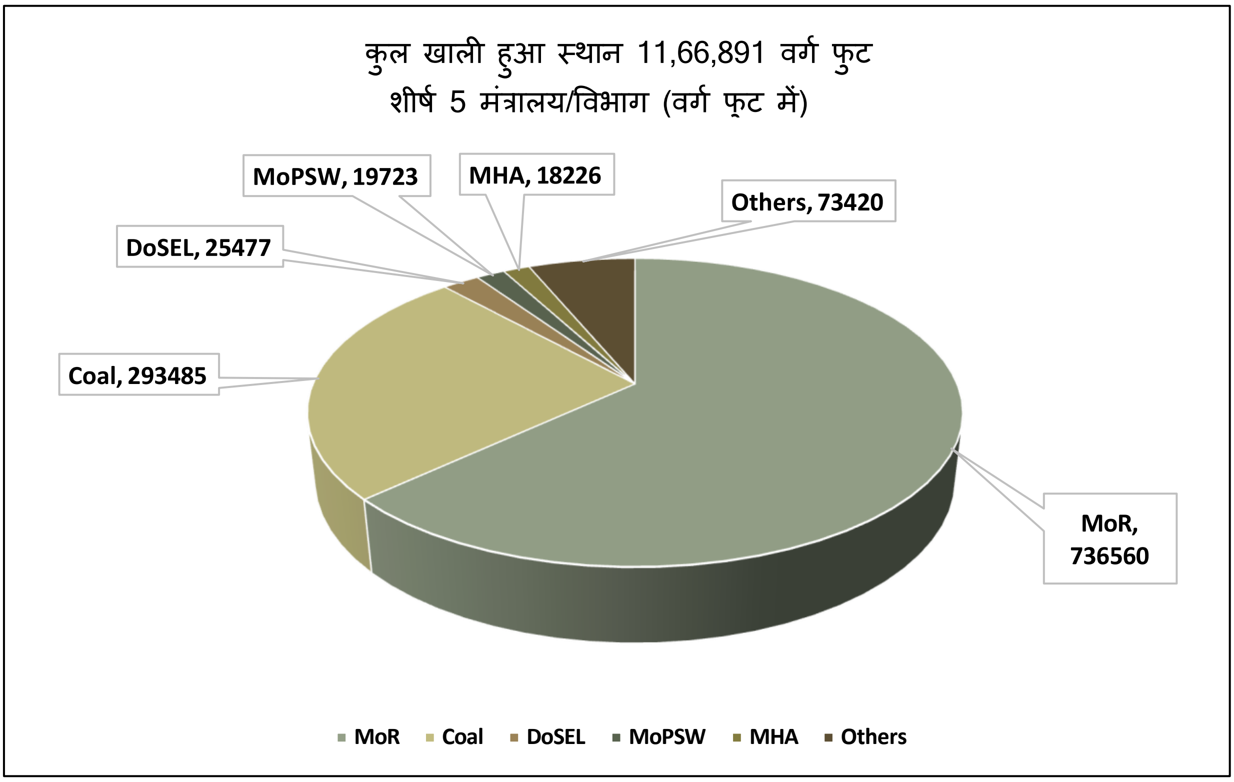

क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित राजस्व

- **रेल मंत्रालय**: जून, 2025 में अर्जित कुल राजस्व 35,23,40,087 रुपये है। अर्जित राजस्व के अनुसार शीर्ष 3 जोन इस प्रकार हैं : -

क्र. सं.	क्षेत्र	अर्जित राजस्व (रुपये में)
1.	पूर्व मध्य रेलवे	15,71,00,000
2.	पूर्वी रेलवे	6,70,00,000
3.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	6,54,15,186

- **कोयला मंत्रालय**: मई, 2025 में कुल राजस्व 10,18,39,969 रुपये अर्जित हुआ। राजस्व अर्जित करने वाली शीर्ष 3 जोन इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	स्थल/कार्यालय	अर्जित राजस्व (रुपये में)
1.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,51,42,874
2.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,95,62,425
3.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,43,17,081

- **भारी उद्योग मंत्रालय**: जून, 2025 में कुल राजस्व 5,71,48,129 रुपये अर्जित हुआ। राजस्व अर्जित करने वाली शीर्ष 3 जोन इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	स्थल/कार्यालय	अर्जित राजस्व (रुपये में)
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	5,42,23,366
2.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,94,280
3.	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया	8,35,020

5.4 स्वच्छता अभियान स्थल (जून 2025)

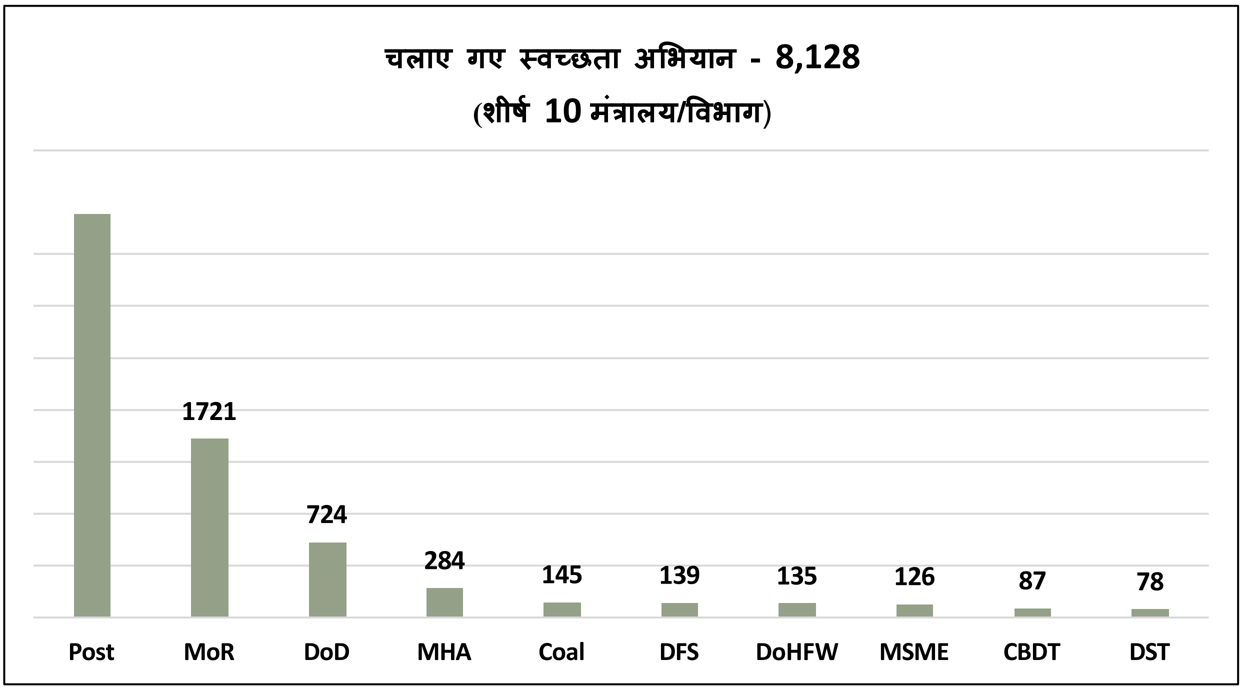

कुल 8,128 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिनमें से लगभग 50% अकेले डाक विभाग द्वारा चलाए गए, जिसके बाद रेल मंत्रालय और रक्षा विभाग का स्थान रहा - जो इन विभागों द्वारा स्वच्छता पहलों में मजबूत और निरंतर भागीदारी को दर्शाता है।

5.5 छँटाई की गई फिजिकल फाइलें (जून, 2025)

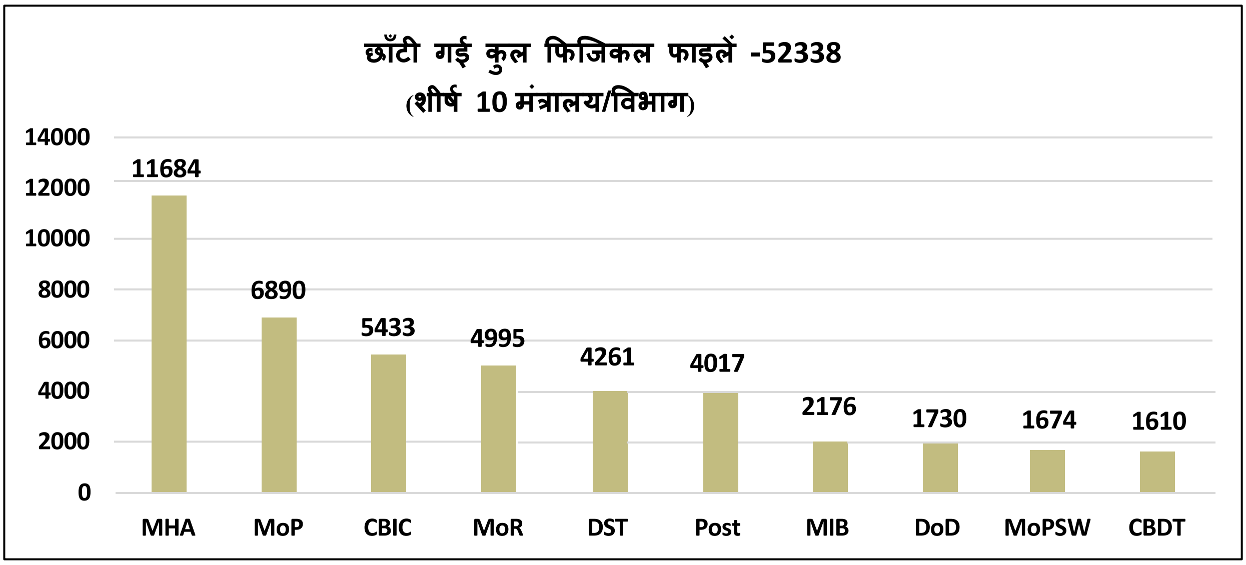

छंटाई की गई **52,338** फिजिकल फाइलों में से, गृह मंत्रालय ने 11,684 फाइलों की छंटाई करके पहला स्थान प्राप्त किया, उसके बाद विद्युत मंत्रालय और सीबीआईसी का स्थान रहा। यह दर्शाता है कि प्रमुख मंत्रालय अव्यवस्था को दूर करने और फिजिकल फाइल प्रबंधन में सुधार लाने की दिशा में मजबूत कदम आ रहे हैं।

6 पहले - बाद में

मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए चित्रात्मक साक्ष्य – जून, 2025

पहले

बाद में

स्क्रैप निपटान - अपशिष्ट प्रबंधन, सुलभ कार्यालय स्थान के माध्यम से सौंदर्य और उपयोगिता को बढ़ाना: **वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र, कोलकाता, डीएई।**

पहले

बाद में

भारी जल बोर्ड, मुंबई में भंडारण स्थान का उपयोग करने के लिए पुरानी फाइलों की कुशलतापूर्वक छंटनी की गई; **डीएई**

पहले

बाद में

कार्यालय स्थान की स्वच्छता और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना- **गोला शाखा - बैंक ऑफ बड़ौदा, झारखंड; डीएफएस**

पहले

बाद में

अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान (एआईआईएसएच), मैसूर; डीएचएंडएफडब्ल्यू में कार्यालय स्थान के कुशल उपयोग के लिए स्क्रैप को हटाना

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालाक्कड़, **केरल** में फैक्ट्री स्वागत कक्ष का नवीनीकरण;

पहले

बाद में

कैफेटेरिया, ट्रांजिट हाउस, सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता में कार्यालय कैफेटेरिया के लिए अप्रयुक्त स्थान का कुशलतापूर्वक उपयोग; **कोयला मंत्रालय**

7 सर्वश्रेष्ठ परिपाटियां - नागरिक अभिमुख परिपाटियां

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम, गुवाहाटी; डीएच एंड एफडब्ल्यू के ओपीडी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

थैलेसीमिया बाल सेवा योजना कार्यशाला का आयोजन **सीआईएल, नई दिल्ली; कोयला मंत्रालय** द्वारा किया गया

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और **डीएफएस** में हरित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक कचरा हटाया।

8 मंत्रालयों/विभागों का मापदंड - वार कार्य निष्पादन

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

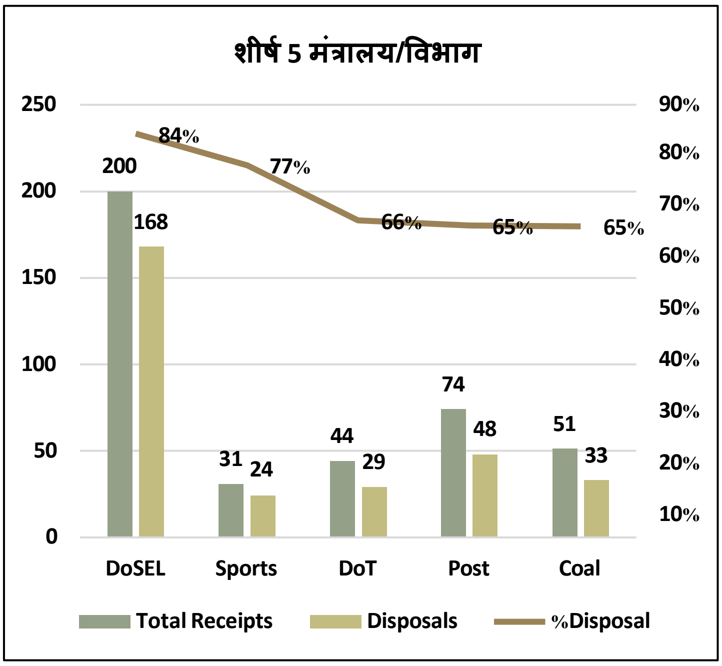

संसदीय आश्वासन

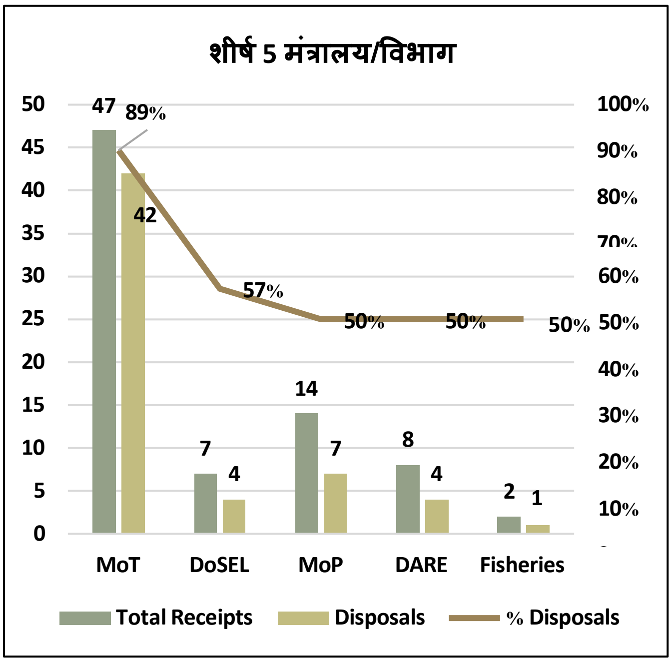

आईएमसी से प्राप्त पत्र

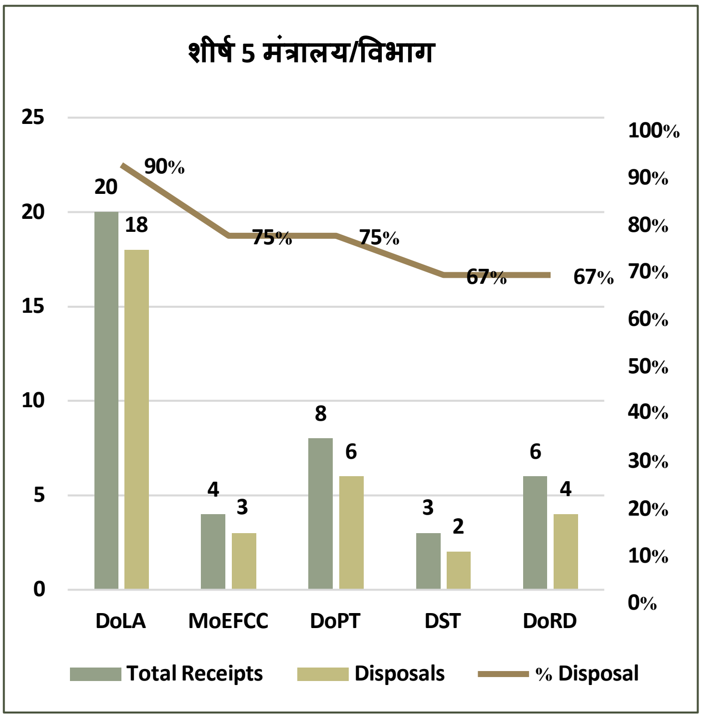

राज्य सरकार से प्राप्त पत्र

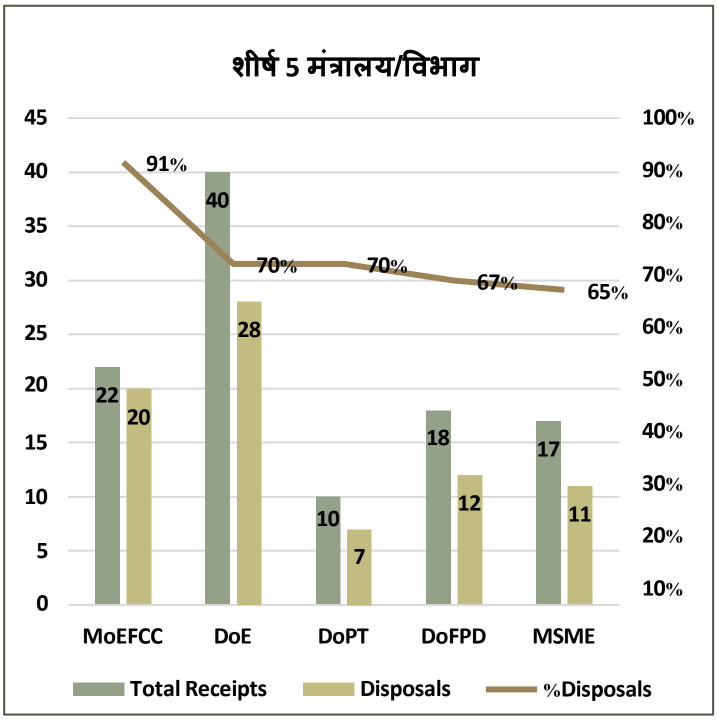

पीएमओ से प्राप्त पत्र

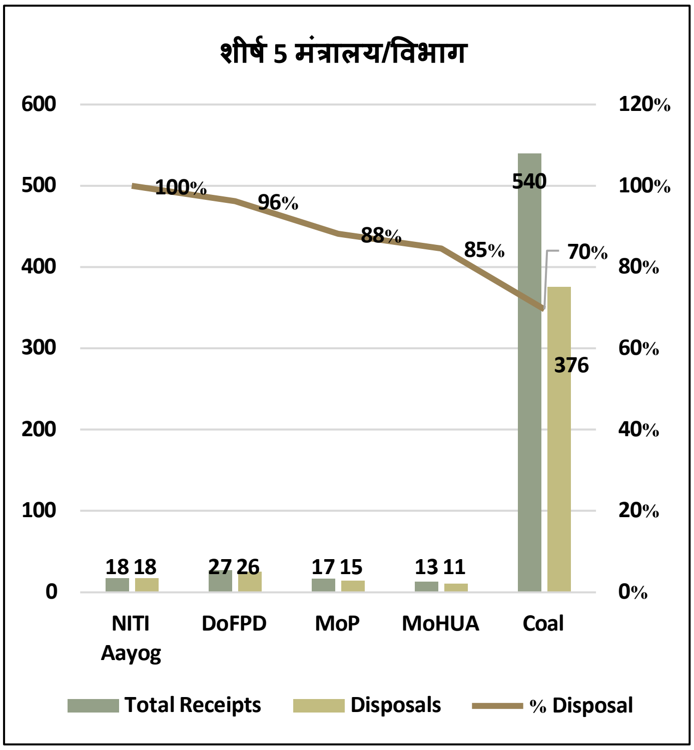

लोक शिकायतें

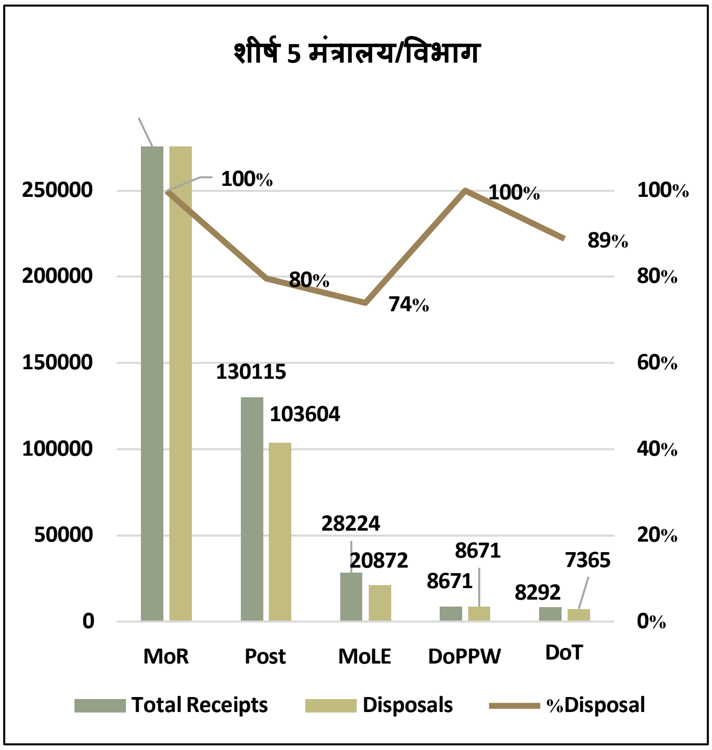

छंटाई की गई फाइलें

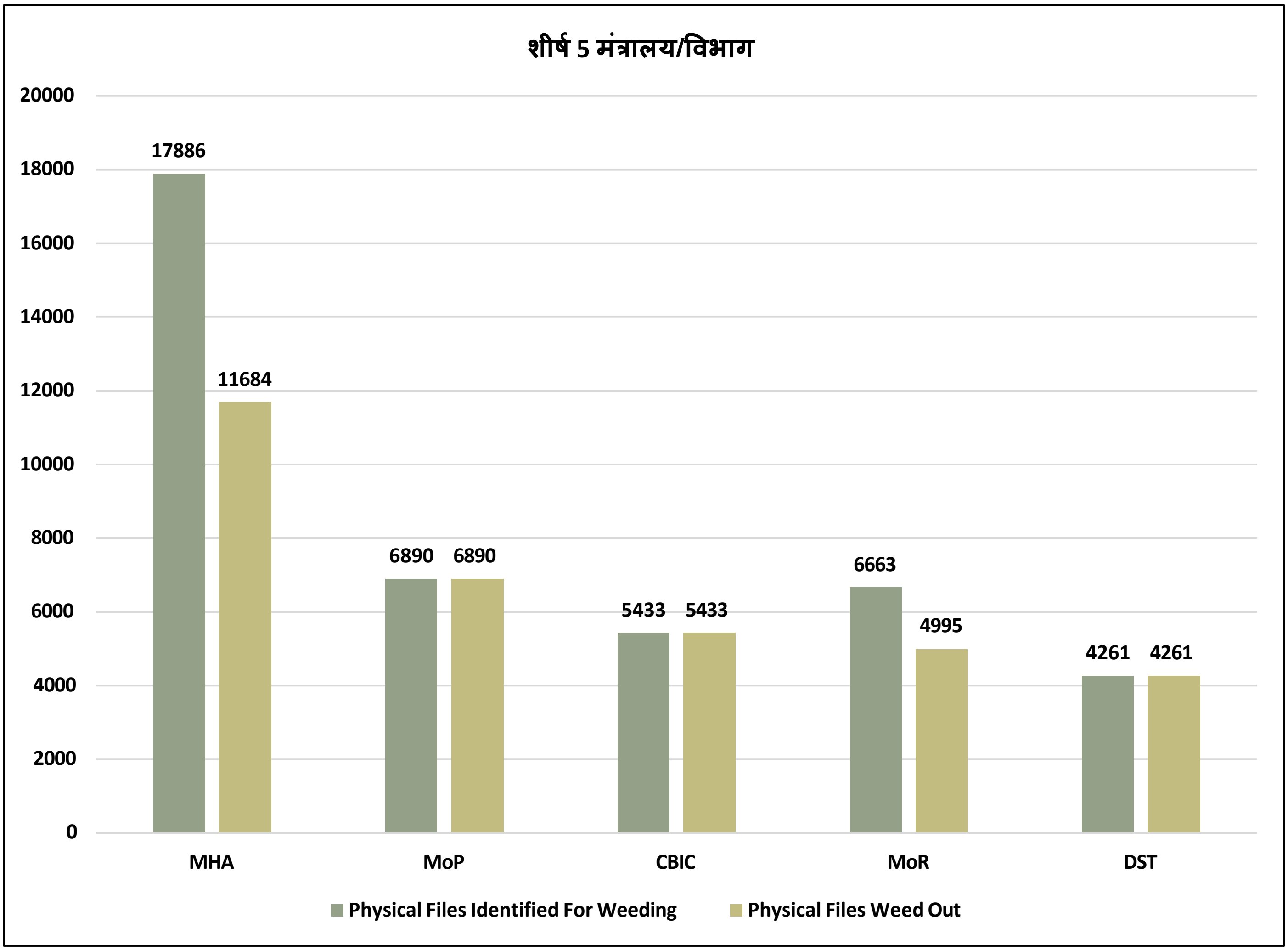

9 मुख्य केंद्र बिंदु : डाक विभाग

परिचय

डाक विभाग, 31.03.2024 तक 1,64,987 डाकघरों के अपने नेटवर्क के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। इस आधुनिक डाक नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 1727 में हुई थी, जब कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया गया। अपनी अद्‌वितीय पहुँच के साथ, भारतीय डाक भारत में संचार, वित्तीय समावेशन और सामाजिक कल्याण का एक प्रमुख प्रवर्तक बना हुआ है। प्रौद्‌योगिकी और नवाचार को अपनाकर, यह निरंतर विकसित हो रहा है तथा शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों की आबादी को निर्बाध सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

डाक विभाग के मुख्य कार्य और गतिविधियाँ

(1) **मेल एवं प्रेषण सेवाएं:**

(क) डाक विभाग का प्राथमिक कार्य, पूरे भारत में डाक की प्रोसेसिंग करना, उसकी ढुलाई करना और डाक बांटना है।

(ख) यह धन प्रेषण सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे देश भर में सुरक्षित वित्तीय लेनदेन संभव हो पाता है।

(2) **वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा:**

(क) एक सदी से भी अधिक समय से, भारतीय डाक बैंकिंग (डाकघर बचत बैंक) और बीमा सेवाएँ (डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा) प्रदान करता रहा है।

(ख) यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी मनरेगा और अन्य केंद्रीय/राज्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वेतन का वितरण करता है।

2. विशेष अभियान 4.0 (02.10.2024 से 31.10.2024) के दौरान डाक विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

2.1 02.10.2024 से 31.10.2024 की अवधि में उपलब्धि

(1) वर्ष के दौरान विभाग द्‌वारा स्वच्छता के प्रति अपनाई गई परिपूर्णता एप्रोच के तहत पूरे नेटवर्क में स्वच्छता अभियान चलाए गए और 46,029 वर्ग फुट जगह मुक्त कराई गई।

(2) 70,000 से अधिक पुरानी फाइलें और ई-फाइलें हटाई गईं, एक लाख से अधिक लोक शिकायतों और 1600 सीपीग्राम्स अपीलों का निपटारा किया गया।

ग्राहक अभिमुख प्रमुख डिजिटल पहलें

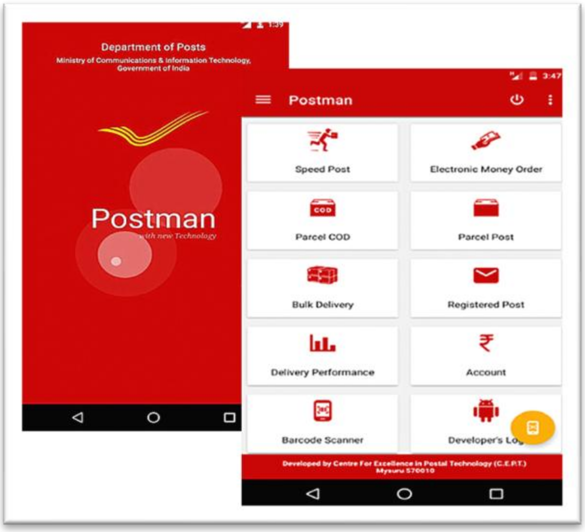

पोस्टमैन मोबाइल एप्लिकेशन (पीएमए): पहले, संबंधित वस्तुओं की डिलीवरी का अपडेट, ऑफ़लाइन मोड में किया जाता था और डिलीवरी की जानकारी, ट्रैकिंग रिपोर्ट में तभी अपडेट होती थी, जब डाकिया दिन भर की डिलीवरी पूरी करने के बाद उसे सिस्टम में दर्ज करता था। केंद्रीय सर्वर में अपडेट में देरी के कारण किसी वस्तु की डिलीवरी स्थिति की विजिबिलिटी और भी सीमित हो जाती थी। स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्रों, पार्सल आदि की डिलीवरी की जानकारी लगभग वास्तविक समय पर अपडेट करने के लिए पोस्टमैन मोबाइल एप्लिकेशन शुरू की गई।

जन संपर्क - डाक चौपाल: डाक चौपालों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएँ नागरिकों के द्वार तक पहुँचें, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें और सामुदायिक सहभागिता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ प्रभावी सेवा सुपुर्दगी को बढ़ावा दें। डाक चौपालों की सफलता न केवल संख्या में परिलक्षित होती है - इसकी शुरुआत (1 सितंबर 2023) से 01.07.2025 तक **देश भर में 58,340 से अधिक डाक चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें लगभग 41.66 लाख लोगों ने भाग लिया है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी न केवल सराहनीय रूप से 45% रही है** - बल्कि सेवा सुपुर्दगी, नागरिक सहभागिता और वित्तीय सशक्तिकरण पर उनके ठोस प्रभाव में भी परिलक्षित होती है।

क. झलकियां

स्वच्छता

स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते कर्मचारी

तेलंगाना डाक मंडल

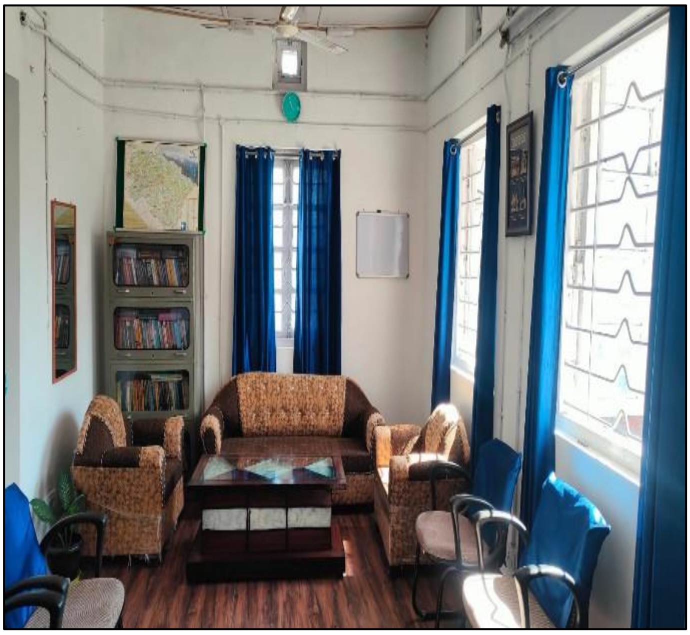

स्थान के पुन: उपयोग की कला: **उत्तराखंड के पौड़ी मंडल** में एक पुस्तकालय की स्थापना;

डाक विभाग

स्थान के पुन: उपयोग की कला: **बेंगलुरु, कर्नाटक** में एक सायंकालीन डाकघर की स्थापना; **डाक विभाग**

कार्य करने के स्थान में बढ़ोत्तरी

शेओराफुली मुख्य डाक घर, पश्चिम बंगाल में एक उल्लेखनीय परिवर्तन, कार्यालय के वातावरण को बेहतर बनाना और एक स्वच्छ, अधिक कुशल कार्यस्थल सुनिश्चित करना; **डाक विभाग**

कंडी, पश्चिम बंगाल में डाक क्वार्टरों का उल्लेखनीय परिवर्तन, आवासीय वातावरण को बेहतर बनाना और अधिक स्वच्छ, अधिक कुशल रहने की जगह सुनिश्चित करना; **डाक विभाग**

अपशिष्ट से धन

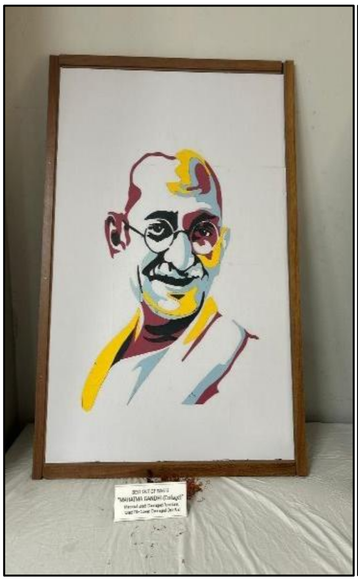

कचरे को कलाकृति के उल्लेखनीय नमूने में बदलना **पश्चिम बंगाल सर्किल** द्वारा स्क्रैप सामग्री से बनाया गया चरखा और महात्मा गांधी की तस्वीर; **डाक विभाग**

योगायोग भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लाउंज के सौंदर्यीकरण के लिए कैरेबियन नाव का उपयोग किया गया; **डाक विभाग**

दीवार कला के माध्यम से दीवारों का सौंदर्यीकरण, **छायगांव एसओ, असम; डाक विभाग**

दीवार कला के माध्यम से दीवारों का सौंदर्यीकरण, **चोटिला एसओ सुरेंद्रनगर, गुजरात; डाक विभाग**

10. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर कार्यालय ज्ञापन

डॉ. टी.वी. सोमनाथन
Dr. T.V. Somanathan

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

D.O. No. 502/2/2/2021-CA.V

27th November, 2024

Dear Secretary,

As you are aware, many initiatives have been undertaken in the recent years to make governance more responsive, accountable and transparent. The initiative for Increasing Efficiency in Decision Making, implemented since 2021, is a step in the same direction. It aims at achieving flatter and leaner organizational structures by putting in place appropriate delegation at various levels, rationalizing workload, thereby speeding up decision-making while increasing the productivity and efficiency of officers.

2. These measures have been incorporated into the Central Secretariat Manual of Office Procedure, 2022 wherein, it is emphasized that, each Ministry/Department will review the instructions on levels of disposal and channel of submission, keeping the number of levels to the minimum by delegating powers to lower formations. To facilitate quicker decision-making, the channels of submission should not be more than four.

3. However, it is observed that delayering is not being implemented in true spirit and a trend of increasing the channels of submission is observed in some Ministries/Departments. This is against the essence of the reforms undertaken so far and creates potential delays in file processing.

4. To sustain the measures undertaken as a part of Increasing Efficiency in Decision Making, you are advised to review the levels of disposal and channel of submission in your Ministry/Department and ensure that the levels do not exceed four and that the Special Secretary/ Additional Secretary/ Joint Secretary function independently as bureau heads.

5. I request you to devote your personal attention to this matter and ensure that these measures are implemented in letter and spirit, thereby fostering speedy and efficient decision making in Government.

With best wishes,

Yours sincerely,

(T.V. Somanathan)

To,

All Secretaries to Government of India

Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004
Tel.: 011-23016696, 23011241 Fax : 011-23018638 E-mail : cabinetsy@nic.in

11. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन

No. Q-150122/2024-O&M-DARPG (8885)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhawan, New Delhi
Dated: 17th December 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Continuation of campaign for Swachhata and Reducing pending matters to the Minimum Possible in Government.

It has been decided that as a sequel to the month-long Special Campaign 4.0 for Swachhata and disposal of pending matters conducted from 2nd October 2024 to 31st October 2024, the campaign has to be institutionalized and the thrust of the campaign should be maintained throughout the year. Accordingly, the following actions may be taken up by Ministries/Departments on a regular basis in order to keep the pendency to minimum possible:

(i) The system of Special Campaign Portal and Nodal Officers will continue to be operational to oversee the institutionalization / continuation of activities covered in the Special campaign.

(ii) All Ministries/Departments may dedicate 3 hours every week for continuation of activities covered in the Special campaign across all offices of Ministries/ Departments.

(iii) Nodal Officers of each Ministry may review the progress of activities on a weekly basis and the Secretary of the Ministry/ Department may review the progress on a monthly basis.

(V. Srinivas)
Secretary to the Government of India

To

All Secretaries of the Government of India

Copy for information to:

1. Principal Secretary to the PM
2. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi (Ms. Kavita Singh, JS)
3. All Nodal Officers of Special Campaign 4.0

Copy to:

Senior Technical Director, NIC, DARPG

12. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन

No. Q-15012/2/2024-O&M-DARPG (e-8885)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhawan, New Delhi
Dated 31st December, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Continuation of campaign for Swachhata and Reducing pending matters to the Minimum Possible in Government.

****

In continuation of this Department's Office Memorandum of even No. dated 17.12.2024 (copy enclosed) on the above subject it is informed that the monthly data may be reported by the Nodal Officers on the SCDPM Portal i.e. https://scdpm.nic.in. Nodal Officers can access the SCDPM portal from 3rd January, 2025 and data entry may be completed by 7th of every month.

Encl: As above.

(V. Srinivas)
Secretary to the Government of India

To

All Secretaries of the Government of India

Copy for information to:

1. All Nodal Officers of Special Campaign 4.0
2. Senior Technical Director, DARPG, NIC. — 02/01/25

13. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

MOST IMPORTANT

No.O-16012/6/2017-ARC-DARPG (e2938)
Government of India
Ministry of Personnel, Pensions and Public Grievances
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

6th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan,
Janpath, New Delhi
Dated 17th January, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: eOffice Analytics - regarding.

*****

The undersigned is directed to say that the following guidelines may be adopted by Ministries / Departments for implementation of eOffice in Central Secretariat:

(i) Display their standing orders of delayering/Channels of Submission on their respective e-Office dashboard.

(ii) Review Virtual Private Network (VPN) usage. Non-users may be identified and steps may be taken to deactivate / close the idle account after due examination and process. The NIC teams of Ministries/Departments may approach NIC VPN Division to obtain VPN data and for deactivation of idle VPN accounts.

(iii) Follow the Manual of Office Procedure strictly and to avoid proliferation of part-files on the same subject. 'Common office function codes' as prescribed in Chapter - 6 'File Management System' of CSMOP 2022 are to be followed at the time of opening a new eFile in eOffice.

(iv) Use of Knowledge Management System (KMS) for managing the OM's Circulars, Orders etc. and further adding them as references in eFiles. Further, a list of all files (Division-wise/bureau-wise), in PDF, may be placed in the KMS for reference of all so as to avoid creation of multiple files in the same Head or part files.

(v) Review the Designation Master in Personal Information Management System (PIMS) and identify the designations related to Personal Staff of officers. Based on the list of designations received from the Ministries / Departments, personal staff of officers will be removed from the counts of

13. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

-2-

(vii) Review the Basic File Head and notify the standardized Heads based on the relevant subjects of the Ministry/Department. Based on the list of Heads received from the Ministries/Departments, a consolidated list of Heads will be prepared which may be considered as standard Subjects to fetch the Subject-wise pendency.

(viii) The Ministries/Departments who process statutory clearance for various projects such as Ministry of Environment, Forest and Climate Change may provide expected time for clearance, so that the processing time of such files may be noticed.

(ix) E-Office Analytics to be developed to indicate file pendency at each level, to identify time delays and pendency. Emphasis to be given to identifying subject specific pendency across Ministries/Departments.

2. This issues with the approval of Secretary, DARPG.

(Sunil K. Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.011-23440371
email: sunilk.singh73@nic.in

To

Secretaries to the Govt. of India

Copy to:

1. DG, NIC
2. Shri M.K. Mishra, DDG, NIC email: mk.mishra@nic.in
3. Shri Kapil Kumar Sharma, Sr. Director (IT), NIC
4. eOffice-PMU, NIC

Copy for information to:

PSO to Secy. (AR&PG)/PA to JS (SC) /DS (eOffice)

अनुलग्नक I: अपलोड नहीं किए गए आँकड़े

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1	निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
2	राजभाषा विभाग
3	राजस्व विभाग
4	अंतरिक्ष विभाग
5	युवा मामले विभाग
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
7	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
8	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
9	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
10	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
11	जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुलग्नक II- संकेताक्षरों की सूची

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर)
2.	सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
3.	डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
4.	डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5.	डीएआरई	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
6.	डीए एंड एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
7.	डीएएच	पशुपालन, डेयरी विभाग
8.	डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
9.	डीबीटी	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
10.	डीसीपी	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
11.	डीओसी	वाणिज्य विभाग
12.	डीओसीए	उपभोक्ता मामले विभाग
13.	डीओडी	रक्षा विभाग
14.	डीओडीपी	रक्षा उत्पादन विभाग
15.	डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
16.	एमओ डोनर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
17.	डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
18.	डीईपीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
19.	डीईएक्सडब्ल्यू	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
20.	डीओई	व्यय विभाग
21.	डीओएफ	उर्वरक विभाग
22.	डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
23.	फिशरीज	मत्स्य पालन विभाग
24.	डीओएफपीडी	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
25.	डीएच एंड एफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

26.	डीएचआर	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
27.	डीएचई	उच्चतर शिक्षा विभाग
28.	दीपम	विनिवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
29.	डीओजे	न्याय विभाग
30.	डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
31.	डीओएलए	विधि कार्य विभाग
32.	डीएमए	सैन्य कार्य विभाग
33.	डीओएल	राजभाषा विभाग
34.	डीपीपीडब्ल्यू	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
35.	डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
36.	डीओपीएच	औषध विभाग
37.	पोस्ट्स	डाक विभाग
38.	डीओपीई	लोक उद्यम विभाग
39.	डीओआर	राजस्व विभाग
40.	डीओआरडी	ग्रामीण विकास विभाग
41.	डीओएसईएल	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
42.	डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
43.	डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
44.	डीओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
45.	डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
46.	स्पोर्ट्स	खेल विभाग
47.	डीओटी	दूरसंचार विभाग
48.	डीओडब्ल्यूआर एंड आरडी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
49.	डीओवाईए	युवा कार्यक्रम विभाग
50.	एलडी	विधायी विभाग
51.	आयुष	आयुष मंत्रालय
52.	मोका	नागर विमानन मंत्रालय
53.	कोल	कोयला मंत्रालय

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
54.	को-ऑपरेशन	सहकारिता मंत्रालय
55.	एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
56.	एमओसी	संस्कृति मंत्रालय
57.	डीओडीडब्ल्यूएस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
58.	एमओई	शिक्षा मंत्रालय
59.	एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
60.	माइटी	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
61.	एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
62.	एमईए	विदेश मंत्रालय
63.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
64.	एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
65.	एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
66.	एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
67.	एमएचए	गृह मंत्रालय
68.	एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
69.	एमआईबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
70.	एमओएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
71.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
72.	एमओएम	खान मंत्रालय
73.	एमओएमए	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
74.	एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
75.	एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
76.	एमपीए	संसदीय कार्य मंत्रालय
77.	एमओपीएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
78.	एमओपी	विद्युत मंत्रालय
79.	एमओआर	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
80.	एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
81.	एमओपीएस डब्ल्यू	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
82.	एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
83.	एमओएसपी आई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
84.	एमओएस	इस्पात मंत्रालय
85.	एमओटी	वस्त्र मंत्रालय
86.	टूरिज़्म	पर्यटन मंत्रालय
87.	एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
88.	एमओडब्ल्यू सीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
89.	एमओवाईए एस	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
90.	नीति आयोग	नीति आयोग

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग

भारत सरकार

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - **110001**